

[2023] 2 एस. सी. आर. 339

केरल राज्य बनाम।

ए.

मेसर्स एके फ्लेवर्स एंड एरोमेटिक्स लिमिटेड (सिविल अपील संख्या)।7330 2009)

फरवरी 02,2023

बी.

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचनाएँ:कर छूट अधिसूचना एस. आर. ओ. 1727/1993-कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर लगाने से पांच साल की अवधि के लिए छूट-छूट का अधिकार-छूट की शुरुआत, केंद्र सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी की तारीख से या उत्पादन शुरू होने की तारीख से-मूल्यांकन प्राधिकरण ने 16.12.1993 से पांच साल की अवधि को कम कर दिया-आयोजित:एक सादे पठन पर दिनांकित 16.12.1993 पत्र केवल एक अनुमति प्रतीत होता है-अनुमति पत्र में मानक शर्तें होती हैं जो वाणिज्यिक सहमति "आशय पत्र" का वर्णन करती हैं-छूट के लाभ को सक्षम करने के लिए स्पष्ट शब्दों में वास्तविक अनुमोदन 27.10.1994 पर जारी किया गया था, जब केंद्र सरकार द्वारा "ग्रीन कार्ड" जारी किया गया था-इस प्रकार, "अनुमोदन" शब्द दिनांकित 27.10.1994 पत्र में जारी किया गया था-अनुमोदन की तारीख 27.10.1994 थी और वह अधिसूचना के तहत छूट देने के लिए गणना योग्य तिथि होगी और निर्धारिती 27.10.1994 के बाद छूट का लाभ उठा सकता था-निर्धारिती का मामला कि उसने केवल 10.10.94 पर उत्पादन शुरू किया जो गणना योग्य तिथि है, प्रेरक नहीं है।

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील No.7330।

2005 के एसटीआर No.388 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.11.2008 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

के साथ

सिविल अपील Nos.7329/2009,7328/2009 और 1383/2023।

पल्लव सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. विनोद, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

- जी.
- न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
- एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०
1. एस. एल. पी. (सी) संख्या 36394/2011 में दी गई छुट्टी।
 2. इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए और अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा था कि व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ए

- एच.
- 339
- 340
- सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
- [2023] 2 एस सी आर।
- एस. आर. ओ. 1727/1993 जो केरल राज्य द्वारा जारी एक छूट अधिसूचना है, शामिल है।

3. अपीलों को राज्य (राजस्व) के साथ-साथ औद्योगिक इकाई दोनों द्वारा प्राथमिकता दी गई है।संक्षिप्त विवाद छूट की पात्रता के संबंध में है।राजस्व का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी की तारीख से लेकर परियोजना की मंजूरी तक पांच साल की छूट की सीमा शुरू होनी थी।दूसरी ओर कर निर्धारकों ने तर्क दिया था कि छूट उत्पादन शुरू होने की तारीख से शुरू होगी।

- बी.
4. संबंधित छूट प्रदान करने वाली संबंधित अधिसूचना इस प्रकार है:
- “अनुसूची-VI

सी.

जिन वस्तुओं की औद्योगिक उपक्रमों/निर्माताओं/विक्रेताओं को बिक्री या औद्योगिक उपक्रमों/निर्माताओं द्वारा वस्तुओं की खरीद को उपखंड (5) खंड I के तहत छूट दी गई है।

डी.

ई.

एफ.

5. आकलनकर्ताओं ने काली मिर्च, अदरक, हल्दी आदि कच्चे माल की खरीद पर कई वर्षों तक कर लगाने से छूट का दावा किया। मूल्यांकन प्राधिकरण ने छूट प्रदान करते हुए उन वर्षों का मूल्यांकन पूरा किया। इसके बाद, इसने मूल्यांकन को फिर से खोलने का प्रयास किया। अंततः, पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में जुर्माना लगाया गया। इस बीच राज्य ने अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में न्यायाधिकरण की टिप्पणियों पर सवाल उठाया था। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि राजस्व के रुख में कोई तर्क नहीं था कि कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर से छूट की अवधि इकाई की स्थापना से पहले कम की जानी चाहिए। आकलन प्राधिकरण ने

16.12.1993 से पाँच साल की अवधि को कम कर दिया था। उच्च न्यायालय में संशोधन ए

जी.

एच.

स्टेट ऑफ केराला बनाम एम/एस एके फ्लेवर्स एंड एरोमेटिक्स लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ए.

341

समय की पाबंदी थी। उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। नतीजतन राजस्व अपील में है और 2011 के एसएलपी (सी) No.36394 से उत्पन्न अपील निर्धारिती द्वारा दायर की जाती है। डिवीजन बेंच ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया था, भले ही एकल न्यायाधीश ने जुर्माने को कम करके कुछ हद तक राहत दी थी। 6. राजस्व की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अधिसूचना की शर्तों पर भरोसा करते हुए कि वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार ने वास्तव में, अपनी मंजूरी दे दी थी जब निर्धारिती को 16.12.1993 पर अनुमति पत्र जारी किया गया था, जिसने इसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात और तैयार उत्पाद का निर्यात शुरू करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती ने दिसंबर, 1993 के बाद कच्चे माल के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी भी खरीदी है और इस परिस्थिति में 1995 से पहले की अवधि के लिए इस तरह की छूट का लाभ देना विरोधाभासी होगा। इसलिए, यह श्री पल्लव सिसोदिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

द्वारा प्रस्तुत विद्वान गया था कि वर्तमान मामले में शुरू होने की तारीख एक अप्रासंगिक कारक है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोसेफ मार्कस ने आग्रह विद्वान कि 16.12.1993 दिनांकित पत्र केवल अनुमति का है और वास्तव में, एक आशय पत्र था। केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी नहीं दी गई थी जैसा कि इसकी शर्तों में स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता ने वास्तव में दिनांकित "ग्रीन कार्ड" की एक प्रति पर भरोसा किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इकाई को निर्यात उन्मुख इकाई के लिए भारत सरकार की विशेष योजना के तहत अनुमोदित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह देखते हुए कि यह दस्तावेज़ 1994 में जारी किया गया था, निर्धारिती ने अपना संयंत्र लगाने में कुछ समय लिया जिसके बाद उसने 01.10.1995 पर उत्पादन शुरू किया और यह कि छूट शुरू करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है।

बी.

सी.

डी.

ई.

7. इस मामले में विवाद को तय करने की कुंजी केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शब्द के साथ जोड़ा जाने वाला अर्थ है जो 1993 के एस. आर. ओ. 1727 में आता है। छूट अधिसूचना का प्रासंगिक भाग, जो माल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले 100% EO के संबंध में केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम की पहली अनुसूची की मद 97 के घटक भागों, उपकरणों आदि सहित कच्चे माल, संयंत्र और मशीनरी पर कर का भुगतान करने से निर्धारिती को राहत देता है, निम्नानुसार है:

एफ.

“छूट केंद्र सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों के अनुमोदन की तारीख को पांच साल की अवधि के लिए होगी।”

8. इस मामले में, एक सादे पठन पर 16.12.1993 दिनांकित पत्र केवल अनुमति प्रतीत होता है। उन वस्तुओं को निर्धारित करने के अलावा जिनके संबंध में ई. ओ. यू. या इकाई छूट का दावा कर सकती है, अन्य शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल था कि पूरे उत्पादन को सामान्य मुद्रा क्षेत्र/कठिन मुद्रा क्षेत्र के देशों को निर्यात किया जाना था और मूल्यवर्धन न्यूनतम 67 प्रतिशत होगा और बाहरी वाणिज्यिक उधार का सहारा लेने की स्थिति में इकाई को मूल्यवर्धन बनाए रखना होगा।

जी.

एच.

[2023] 2 एस सी आर।

9. इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं की सीमा में छूट का भी संकेत दिया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, अनुमति पत्र में मानक शर्तें थीं जो वाणिज्यिक सहमति "आशय पत्र" का वर्णन करती थीं।

10. केंद्र सरकार के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारिती को जारी किए गए दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर दी गई अनुमति थी। इसलिए, इसे आशय पत्र के रूप में वर्णित किया गया था। छूट के लाभ को सक्षम करने वाले स्पष्ट शब्दों में वास्तविक अनुमोदन 27.10.1994 पर जारी किया गया था, जब केंद्र सरकार द्वारा "ग्रीन कार्ड" जारी किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले में "अनुमोदन" शब्द दिनांकित 27.10.1994 पत्र में जारी किया गया था।

बी.

सी.

11. इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि "अनुमोदन" शब्द का संबंध केंद्र सरकार द्वारा असंदिग्ध अनुमोदन से होना चाहिए जो वर्तमान मामले में 27.10.1994 पर दिया गया था।

12. इसलिए, निर्धारिती 27.10.1994 के बाद छूट का लाभ उठा सकता था।

13. निर्धारिती का यह तर्क कि उसने केवल 01.10.1994 को प्रस्तुत करना शुरू किया, जो इस न्यायालय की राय में गणना योग्य तिथि है, प्रेरक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुमोदन देते समय, हर तरह से निर्धारिती को उस आवश्यकता के बारे में बताया गया था जिसे उसे पूरा करना है। यदि किसी मामले में इकाई धारक आगे नहीं बढ़ने या उत्पादन शुरू नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो उसे इस तरह की निष्क्रियता के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

14. इन परिस्थितियों में, निर्धारिती का यह तर्क कि शुरू होने की तारीख वह तारीख होनी चाहिए जब छूट भी निर्धारित की जा सके, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के विवाद के व्यवहार्य नहीं होने का एक और कारण यह है कि यह कार्यवाही के मूल्यांकन के संबंध में व्यक्तिपरकता पैदा करता है। किसी दिए गए मामले में, इकाई धारक सतर्क हो सकता है और अपनी इकाई को जल्दी स्थापित कर सकता है, जबकि एक अन्य मामले में, संबंधित इकाई धारक को वापस रखा जा सकता है या अपने पैरों को खींचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप इकाई उत्पादन शुरू नहीं कर सकती है। बाद के मामले में, हालांकि यह सुरक्षित

अनुमोदन हो सकता है, उत्पादन शुरू करने में देरी को छूट के साथ पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए।

एफ.

15. उपरोक्त कारणों से, न्यायालय का मानना है कि इस मामले में मंजूरी की तारीख 27.10.1994 थी और यह अधिसूचना SRO 1727/1993 के तहत छूट देने की गणना योग्य तारीख होगी।

जी.

16. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

निधि जैन

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एच.